

सेवा में,

मा० मुख्यमन्त्री महोदय

उ० प्र०, लेखनऊ

ज्ञापन

विषय:- लेखपाल संवर्ग की मांगों के सम्बन्ध में स्वयं हस्तक्षेप कर शासनादेश निर्गत कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि लेखपाल संवर्ग, सरकार की विभिन्न नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने पदीय दायित्वों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के कार्यों में सहयोग करता है। शासन/प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों के निर्देशों का पालन अनुशासित सेवक की भांति करते हुए अपने पदीय/शासकीय/सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है तथा जनता की समस्याओं का निस्तारण कराता है। उ० प्र० लेखपाल संघ द्वारा 16 मार्च 2016 को 6 सूत्रीय माँगपत्र महोदय की सेवा में प्रस्तुत किया था तथा समस्याओं को निस्तारित कराने की माँग की गई थी। मा० राजस्व परिषद द्वारा माँगों का परीक्षण एवं वार्ता करने के बाद सहमति व्यक्त करते हुए लेखपाल संवर्ग की ए० सी० पी० विसंगति को दूर करने व लेखपाल संवर्ग के प्रशासनिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भिक वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2800 करने सहित समस्त 6 माँगों के सम्बन्ध में प्रस्ताव संस्तुति सहित दिनांक 16 जून 2016 को मा० प्रमुख सचिव (राजस्व) को भेजे जा चुके हैं। मा० प्रमुख सचिव (राजस्व) द्वारा संवर्ग की माँगों का औचित्य स्वीकार किया गया था, जिसके अनुरूप पत्रावलियाँ सहमति उपरान्त वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग के सम्बन्धित अनुभागों में अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी हैं।

महोदय, उ० प्र० लेखपाल संघ 31337 लेखपालों की पंजीकृत संस्था है। संस्था का सदैव मत रहा है कि अपनी न्यायोचित माँगों को तथ्यात्मक तर्कों के साथ शान्तिपूर्ण तरीके से शासन/परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करते हुये अपने कर्तव्यों को लगातार निभाते रहें। संस्था द्वारा लम्बे समय से इसी नीति पर कार्य करते हुए शासन के विभिन्न पटलों पर वार्ता व पत्राचार द्वारा अपनी न्यायोचित माँगों को निस्तारित कराने का प्रयास किया गया है, परन्तु मा० राजस्व परिषद के संस्तुति सहित प्रस्तावों एवं मा० प्रमुख सचिव (राजस्व) महोदय की सहमति एवं आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् भी अभी तक शासन स्तर से शासनादेश/नियमावली संशोधन निर्गत नहीं किये गये हैं, जिससे संवर्ग में आक्रोश व्याप्त है।

महोदय, उ० प्र० शासन द्वारा विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों, वेतन उच्चीकरण व अन्य माँगों का निस्तारण किया गया है, परन्तु शासन द्वारा लेखपाल संवर्ग की औचित्यपूर्ण माँगों के सम्बन्ध में शासनादेश/नियमावली संशोधन निर्गत न होने के कारण लेखपाल संवर्ग स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है।

महोदय, संवर्ग की मांगें न्यायपूर्ण हैं तथा मा० परिषद व शासन स्तर पर औचित्यपूर्ण मानते हुए संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। संस्था द्वारा माँगों को पूर्ण कराने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। 40 दिन का नोटिस मा० मुख्य सचिव महोदय की सेवा में प्रेषित किया था तथा उसके बाद भी एक सप्ताह तक सांकेतिक आन्दोलन कर शासन/ सरकार का ध्यानाकर्षण करने का प्रयास किया गया परन्तु शासन द्वारा संवर्ग की माँगों के सम्बन्ध में शासनादेश/ नियमावली संशोधन निर्गत नहीं किये जा रहे हैं तथा संस्था के संवर्ग हित में किये जा रहे आन्दोलन में सहभागिता कर रहे सदस्यों पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही कर अपने तानाशाही रवैये का प्रदर्शन किया जा रहा है। 29 अगस्त 2016 को 30 अगस्त को विधान सभा के घेराव के लिए जनपदों से आ रहे लेखपालों की बसों को रास्ते में रोक कर पुलिस/प्रशासन द्वारा संस्था के आन्दोलन को बाधित करने का प्रयास किया गया तथा दिनोंक

30 अगस्त 2016 को संस्था द्वारा महोदय को पूर्व सूचित विधान सभा घेराव के कार्यक्रम में प्रदेश के लेखपालों के द्वारा शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था परन्तु पुलिस द्वारा लेखपालों पर अत्याचार करते हुए लाठीचार्ज किया गया, जिससे सैकड़ों लेखपाल घायल हुये। शासन की यह कार्यवाही अलोकतान्त्रिक व तानाशाहीपूर्ण है। शासन की इस कार्यवाही से संवर्ग बहुत आक्रोशित है। दिनोंक 30 अगस्त 2016 को दोपहर 2 बजे उ०प्र० लेखपाल संघ के शिष्ट मण्डल को वार्ता का निमंत्रण मिला। शिष्ट मण्डल की वार्ता शासन द्वारा संवर्गों की वेतन व वेतन विसंगतियों के निस्तारण हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रदीप भटनागर के साथ वार्ता हुयी, जिसमें उनके साथ मा० प्रमुख सचिव(राजस्व) व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वार्ता में उपस्थित मा० प्रमुख सचिव(राजस्व) श्री अरविन्द कुमार द्वारा यह स्वकार किया गया कि लेखपाल संवर्ग की मांगों के सम्बन्ध में प्राप्त राजस्व परिषद के प्रस्तावों से सहमति व्यक्त करते हुये वित्त विभाग को भेजे जा चुके हैं। इस पर समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप भटनागर, मा० ए०पी०सी०, उ०प्र० शासन द्वारा प्रतिनिधि मण्डल को अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के साथ एक बार पुनः बैठक शीघ्र करायी जायेगी। संस्था शिष्ट मण्डल द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में शासनसदृश निर्गत करने की मांग की जिस पर बैठक में कोई निर्णय न होने के कारण वार्ता निष्फल रही।

महोदय, संवर्ग की मांगों के सम्बन्ध में मा० प्रमुख सचिव (राजस्व) की संस्तुतियों काफी समय से अन्तिम पायदान यथा वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग में लम्बित हैं, उनका परीक्षण/अनुशीलन कर शासनादेश निर्गत किये जाने का समय शासन को नहीं मिला जबकि लेखपालों के द्वारा अपनी न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध में चलाये जा रहे शान्तिपूर्ण आन्दोलन के खिलाफ एस्मा लगाये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत करने में एक दिन का समय भी नहीं लगा। इसने संवर्ग में पूर्व से ही व्याप्त रोष में वृद्धि करने का काम किया है। इसलिए संस्था आन्दोलन को अनवरत जारी रखने के लिए विवश है।

संस्था की मांगें

- 1- लेखपाल संवर्ग में उत्पन्न ए०सी०पी० विसंगति दूर की जाये।
- 2- लेखपाल संवर्ग का पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक एवं शैक्षिक योग्यता स्नातक करते हुये प्रारम्भिक वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2800 किया जाये।
- 3- लेखपाल संवर्ग का कौडर पूर्ववत् जनपद स्तरीय करते हुये, स्थानान्तरण नीति में संशोधन किया जाये।
- 4- पाँच लेखपालों पर एक राजस्व निरीक्षक (क्षेत्र) एवं राजस्व परिषद के पत्र दिनांक 04 अप्रैल 2016 के अनुसार राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) के 626 पदों का सृजन किया जाये और राजस्व निरीक्षक प्रोन्नति एवं नायब तहसीलदार प्रोन्नति हेतु राजस्व परिषद के प्रस्ताव के अनुसार नियमवाली में संशोधन किया जाये।
- 5- ई-डिस्ट्रिक्ट , आई०जी०आर०एस० आदि शासन की विभिन्न योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन के लिये लेखपालों को लेपटॉप तत्काल उपलब्ध कराया जाये।
- 6- एक अप्रैल 2005 से पूर्व चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया जाये तथा 01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त लेखपालों की नई पेंशन योजना में सुधार करते हुये आकस्मिक निकासी और सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर सुनिश्चित पेन्शन की सुविधा प्रदान की जाये।

आन्दोलन का कार्यक्रम

1. 31 अगस्त 2016 से 6 सितम्बर 2016 तक कार्य दिवसों में प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 तक जनपद के सभी लेखपाल पूर्ण कार्य बहिष्कार जारी रखते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे तथा मा० मुख्य मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे।

2. 05 सितम्बर 2016 दिन सोमवार को सायं 6:00 बजे सभी जनपदों में जिला अध्यक्ष/जिला सचिवों के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर कैंडिल मार्च किया जायेगा।
 3. दिनांक 6 सितम्बर 2016 मंगलवार को सभी जनपदों में जिला अध्यक्ष/जिला सचिवों के नेतृत्व में लेखपालों के द्वारा धरना स्थल पर ही "बुद्धि शुद्धि यज्ञ" किया जायेगा।
- महोदय से निवेदन है कि प्रकरण में स्वयं हस्तक्षेप करते हुए आन्दोलन के दौरान की जा रही समस्त उत्पीडनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने तथा संवर्ग की न्यायोचित एवं औचित्यपूर्ण मांगों के सम्बन्ध में मा0 राजस्व परिषद एवं मा0 प्रमुख सचिव (राजस्व) की संस्तुतियों के अनुसार शासनादेश शीघ्र निर्गत करने सम्बन्धी निर्देश सम्बन्धित अधिकारीयों को निर्गत करने की कृपा करें।

न्याय की प्रत्याशा में।

भवदीय

(नाम)
जिला अध्यक्ष

(नाम)
जिला मंत्री